

**बेरोजगारी**

- \*67. श्री ना० स्व० शर्मा :  
 श्री कंवर लाल गुप्त :  
 श्री शारदानन्द :  
 श्री रामगोपाल शान्तवाले :  
 श्री रा० स्व० विद्यार्थी :  
 श्री रा० रा० सिंह देव :  
 श्री ईश्वर रेड्डी :  
 श्री य० अ० प्रसाद :  
 श्री वेदव्रत बरुआ :  
 श्री राणें :  
 श्री राम सिंह अग्रवाल :

क्या अम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार लोगों की संख्या में गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कोई कमी नहीं हुई है ;

(ख) प्रथम द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं में बेरोजगारी को दूर करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और कहां तक बेरोजगारी दूर की जा सकी है ;

(ग) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ये लक्ष्य प्राप्त न किये जा सकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी हां ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना काल में अतिरिक्त नियोजन भवसर जुटाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के लिए क्रमशः 1 करोड़ और 1 करोड़ 40 लाख अतिरिक्त नियोजन भवसर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 95 लाख और 1 करोड़ 45 लाख अतिरिक्त नियोजन भवसर जुटाए गए :

(ग) इस प्रकार निश्चित लक्ष्य लगभग पूरे कर लिए गए थे किन्तु बेरोजगारी की संख्या में कमी नहीं की जा सकी क्योंकि विकास कार्यक्रमों द्वारा बढ़े हुए रोजगार भवसर अम शक्ति में, अपेक्षाकृत अधिक तेज रफ्तार से होने वाली वृद्धि के मुकाबले में कम रहे ।

(घ) वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित कृषि, सिंचाई व बिजली, उद्योग, यातायात और समाज सेवा के क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के द्वारा, आशा है, आने वाले वर्षों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार भवसर प्राप्त होंगे । परिवार नियोजन कार्य-क्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । इसके बावजूद भी कुछ अंशों में बेरोजगारी बनी रहेगी ।

**अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन सम्बन्धी डाक-टिकट**

- \*68. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :  
 श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :  
 श्री न० कु० साठे :  
 श्री सी० मुत्तुस्वामी :  
 श्री हेम बरुआ :  
 श्री जार्ज फरनेन्डोज :  
 श्री मधु तिमयें :  
 श्री हुकन चन्व कछवाय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1968 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन के मद्रास अधिवेशन के भवसर पर जारी किये गये प्रस्तावित डाक-टिकट पर हिन्दी और अंग्रेजी के शब्दों के साथ तमिल शब्द न होने के बारे में तमिलनाडु सरकार ने कोई आपत्ति की थी ;

(ख) क्या मद्रास के मुख्य मंत्री द्वारा डाक-टिकट जारी करने का औपचारिक समारोह रद्द कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराज): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह डाक-टिकट मद्रास के मुख्य मंत्री की प्रार्थना पर जारी किया गया था। इसमें सम्मेलन के 'एम्ब्लेम' का ठीक वैसा ही चित्र दिया गया है जैसा कि उन्होंने भेजा था।

#### LOW PRICE OF FOODGRAINS IN PUNJAB AND HARYANA

\*61. SHRI N. K. P. SALVE:  
SHRI YAJNA DATT SHARMA:  
SHRI Y. S. KUSHWAH:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the stocks of foodgrains particularly of wheat far exceeded the demand in the markets in the States of Haryana and Punjab and are selling at extra-ordinarily low prices;

(b) whether the same commodity is selling at very high prices in the neighbouring States of Delhi and U.P.; and

(c) if so, whether Government propose to readjust the Food Zones in the light of these circumstances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE):

(a) Punjab and Haryana being surplus States, the availability of foodgrains generally exceeds the local demand. The prices of foodgrains including wheat have fallen since October, 1967 in the States of Haryana and Punjab. The falling trend in prices is because of a good *kharij* crop in the case of *kharij* cereals and expectation of a good *rabi* crop in the case of

the State Government, Co-operatives and the F.C.I. make purchases of foodgrains at the procurement prices to ensure that the prices do not fall below the level of the procurement prices.

(b) The prices of wheat in Delhi and U.P. are somewhat higher than in Haryana and Punjab. There is always some difference in prices between the surplus and deficit States.

(c) The matter of zonal restrictions will be considered as usual in the next meeting of the Chief Ministers called to consider *Rabi* Policy.

#### आयातित गेहूँ तथा माइलो के मूल्यों में वृद्धि

\*71. श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के पश्चात् सरकार ने अमरीका से आयात किये गये गेहूँ और माइलो के विक्रय मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति किलो बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस वृद्धि के खिलाफ केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(घ) गेहूँ के मूल्य में उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय भंडार से सप्लाई किए जाने वाले आयातित गेहूँ तथा माइलो के निर्गम मूल्य पहली जनवरी, 1968 से बढ़ा दिये गये हैं।

(ख) आयातित गेहूँ तथा माइलो के निर्गम में क्रमशः 12 पैसे और 8 पैसे प्रति